आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 28.03.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।
- प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के लिए सर्वे पूरा, 1 हजार 490 बाराहमासी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के 40 हजार 504 लाभार्थियों को 01 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि, डीबीटी के माध्यम से वितरित की।
- अल्मोड़ा में गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर गोष्ठी का आयोजन।

केंद्रीय मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22 हजार 919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 91 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह इस साल की पहली जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों और 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सड़क सर्वे

प्रदेश में 250 तक की आबादी वाली बसावटों को बाराहमासी सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके क्रम में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने 8 हजार 750 किलोमीटर लंबी, 1 हजार 490 सड़कों के निर्माण का सर्वे पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के छोटे–छोटे गांवों तक सड़क पहुंचाई जा रही है। अब आबादी के लिए कलस्टर को मानक बनाए जाने से, उत्तराखंड की कम आबादी वाली बसावटों तक भी सड़क पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के चौथे चरण में जल्द काम शुरू किया जाएगा। वहीं, सचिव, ग्राम्य विकास, राधिका झा ने बताया कि सर्वे के बाद इन सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है,

जिसे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, आबादी का निर्धारण राजस्व गांव या पंचायत के आधार पर नहीं, बल्कि, एक निश्चित दायरे में रहने वाली आबादी को जोड़कर किया जाएगा। उत्तराखंड में डेढ़ किलोमीटर के दायरे में मौजूद बसावटों को एक साथ जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे विकासखंड़ों में दस किलोमीटर के दायरे में मौजूद बसावटों को जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा। इसका लाभ उत्तराखंड जैसी छोटी बसावट वाले राज्य को मिलेगा।

बहुउद्देशीय शिविर बागेश्वर

सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में बहुउद्देश्यीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी और मौके पर ही कई लोगों को लाभान्वित किया। शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 4 करोड़ 68 लाख रुपये के चेक भी वितरित किए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए युवा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया।
बहुउद्देश्यीय जन सेवा शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

नंदा गौरी डीबीटी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से नंदा गौरा योजना के 40 हजार 504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 01 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि, डीबीटी के माध्यम से वितरित की। इस योजना से गत 05 वर्ष में 02 लाख 84 हजार 559 लाभार्थियों को 09 अरब 68 करोड़ 64 लाख 51 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। योजना के तहत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11 हजार और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। श्री धमी ने कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।

नमामि गंगे गोश्ठी

अल्मोड़ा में नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला गंगा सुरक्षा समिति और एक संस्था के सहयोग से गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद– यूकॉस्ट के सलाहकार व भू–जल विशेषज्ञ प्रोफेसर जे.एस रावत ने उत्तराखंड की गैर हिमानी नदियों के घटते जल स्तर, सूखती जल धाराओं के कारण और प्रभाव पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए उपाय नहीं ढूंढे गए, तो आने वाले 15– 20 सालों में ये नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी।

जिला गंगा सुरक्षा समिति के सचिव दीपक सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा के लिए कोसी नदी जीवन रेखा है। इसके पुनर्जीवन का कार्य 2017–18 से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि अब इस परियोजना को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है और जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

यातायात प्रतिबंधित

चमोली जिले में नन्दप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के उपचार कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नन्दप्रयाग–चमोली को आज से 14 अप्रैल तक यातायात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी आर.के पाण्डेय ने बताया कि नन्दप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। इस दौरान हल्के वाहनों की आवाजाही चमोली–कोठियाल सैण–नन्दप्रयाग से की जाएगी। वहीं भारी वाहनों के लिए प्रातः 05 बजे से 08 बजे, दोपहर 01 बजे से 02 बजे और रात्रि 06 बजे से 09 बजे आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है।